न्यायधीश रणजीत सिंह के समक्ष

श्रीमती. गीता,-याचिकाकर्ता

बनाम

श्रीमती राज बाला और अन्य,-प्रतिवादी

Crl. विविध. 2007 की संख्या 47145-एम

26 नवंबर, 2008

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973–धारा. 482–भारत का संविधान, 1950–अनुच्छेद 20–घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005–धारा. 12, 19 से 23–2005 अधिनियम के प्रावधानों के तहत याचिकाकर्ता को समन करना–2005 अधिनियम अपराध का संज्ञान लेने की तारीख पर लागू नहीं है–अनुच्छेद 20 यह प्रावधान करके अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है किसी भी व्यक्ति को अपराध के रूप में आरोपित कार्य के करने के समय लागू कानून के उल्लंघन के अलावा किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा - शिकायत के आधार पर संज्ञान लेने की ट्रायल कोर्ट की कारवाई को बरकरार नहीं रखा जा सकता है-

समन आदेश को टिकाऊ ना होने की वजह से रद्द किया जाता है।

यह निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 20 यह प्रावधान करके अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है, कि किसी भी व्यक्ति को अपराध के रूप में आरोपित कार्य के करने के समय लागू कानून के उल्लंघन के अलावा किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा। इस अनुच्छेद के अनुसार, जब कोई निश्चित कार्य उस समय लागू कानून के अनुसार अपराध नहीं होता है जब वह कार्य किया जाता है, तो उस कार्य को करने वाले व्यक्ति को केवल इसलिए किसी अपराध का दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए की बाद में कृत्य को अपराध बनाने के लिए एक कानून बनाया गया है। जब याचिकाकर्ता पर घरेलू हिंसा अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध करने का आरोप लगाया जाता है, जो ऐसे कृत्यों को करने की तारीख पर लागू नहीं है, तो उक्त धाराओं के तहत लगाए गए आरोप संविधान के अनुच्छेद 20(1) के तहत कायम नहीं रह पाएंगे क्यूंकी जब कथित अपराध किए गए थे तब उक्त दंडात्मक प्रावधान अस्तित्व में नहीं थे। वास्तव में, उस समय कोई कानून लागू नहीं था जब याचिकाकर्ता ने कथित तौर पर ये कृत्य किए थे और इसलिए वह संविधान के अनुच्छेद 20(1) के संरक्षण का हकदार होगा।

26 अक्टूबर, 2006 को अधिनियम लागू होने के बाद, अपराध पैदा करने वाले अधिनियम के विभिन्न प्रावधान ऐसे अपराध नहीं होंगे जिसके लिए याचिकाकर्ता पर मुकदमा चलाया जा सकता है। 19 जुलाई, 2006 को इस शिकायत के आधार पर संज्ञान लेने की न्यायालय की कार्रवाई को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। इस प्रकार, सम्मन आदेश कायम नहीं रखा जा सकता है और इसे रद्द कर दिया जाता है।

(पैरा 3)

मनोज कौशिक, वकील, याचिकाकर्ता के लिए।

रोहित आहूजा, वकील, प्रतिवादी नंबर 1 के लिए।

रणजीत सिंह, जे.

(1) श्रीमती. गीता ने एसीजेएम, फ़रीदाबाद द्वारा पारित दिनांक 19 जुलाई, 2006 के नोटिस/समन आदेश को रद्द करने की मांग की है। वह शिकायतकर्ता की विवाहित भाभी है और पलवल में अपने वैवाहिक घर में अलग से रह रही है, लेकिन उसे घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत अभियोजन का सामना करने के लिए बुलाया गया है। संक्षिप्त "अधिनियम")।

(2) याचिकाकर्ता की ओर से किया गया प्राथमिक निवेदन यह है कि उसे अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक अपराध के लिए गलत और अवैध रूप से बुलाया गया है, जो कि उस तिथि पर लागू ही नहीं होता है जिस दिन अपराध का संज्ञान लिया गया था। तदनुसार यह दलील दी गई है कि एसीजेएम, फ़रीदाबाद ने अपराध का संज्ञान लेने में गलती की है, जिस दिन उन्होंने इसका संज्ञान लिया था उस दिन यह कोई अपराध नहीं था।

(3) याचिका में दिए गए कथन से पता चलता है कि अधिनियम 26 अक्टूबर, 2006 को अधिसूचित किया गया था और प्रभावी भी हो गया था। मजिस्ट्रेट ने, हालांकि, याचिकाकर्ता और उसके सह-अभियुक्तों को 19 जुलाई, 2006 को तलब किया है। याचिकाकर्ता और उसके सह-अभियुक्तों को अधिनियम की धारा 12, 19, 20, 21, 22 और 23 के तहत अपराधों के लिए तलब किया गया था। इसे अवैध बताया गया है क्योंकि 19 जुलाई, 2006 को अधिनियम लागू नहीं था और इसलिए अधिनियम के तहत तथाकथित अपराध, जैसा कि देखा गया, क़ानून की किताब में अपराध नहीं थे। हालाँकि योग्यता के आधार पर अन्य प्रस्तुतियाँ भी की गई हैं, लेकिन उन पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। यह तथ्य कि यह अधिनियम 26 अक्टूबर, 2006 से

लागू है, किसी भी गंभीर विवाद में नहीं है। अधिनियम की धारा 1 (3) में प्रावधान है कि अधिनियम उस तारीख से लागू होगा जिसे केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित करेगी। केंद्र सरकार ने नियुक्ति कर दी है 26 अक्टूबर, 2006 वह तारीख है जिस दिन अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1776(ई), दिनांक 17 अक्टूबर, के अनुसार उक्त अधिनियम लागू होगा। । इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अधिनियम 26 अक्टूबर, 2006 से लागू हुआ। प्रतिवादी नंबर 1 के विद्वान वकील ने इस तथ्यात्मक स्थिति पर विवाद नहीं किया, लेकिन फिर भी यह प्रस्तुत करने पर जोर दिया कि मजिस्ट्रेट ने इस मामले में अपराध का सही संज्ञान लिया गया क्योंकि ~अधिनियम वर्ष 2005 का है, यानी, तारीख से पहले, मजिस्ट्रेट ने 19 जुलाई, 2006 को संज्ञान लिया था। बहुत अधिक औचित्य के बिना, वकील ने अपनी दलील के समर्थन में एक मामले का हवाला दिया पं. ऋषिकेश और अन्य बनाम श्रीमती सलमा बेगम[1]। इस मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देखा है कि अधिनियम की शुरुआत कानून बनाने से अलग है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, जैसे ही संसद द्वारा पारित कानून को राष्ट्रपति द्वारा सहमति दी जाती है, वह कानून बन जाता है और अधिनियम का प्रारंभ अधिनियम में ही व्यक्त किया जा सकता है, अर्थात् , जिस क्षण राष्ट्रपति द्वारा सहमति दी गई और राजपत्र में प्रकाशित किया गया, उसी क्षण से यह क्रियाशील हो गया। हालाँकि, यह भी देखा गया है कि जब तक अन्यथा प्रदान न किया गया हो, किसी विशेष समय पर अधिनियम को लागू करने के लिए कार्यकारी या प्रत्यायोजित कानून को शक्ति देकर ऑपरेशन को स्थगित किया जा सकता है। यह समझ में नहीं आता है कि कानून का यह अनुपात उत्तरदाताओं के वकील द्वारा उठाई गई याचिका को कैसे लाभान्वित करेगा। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, अधिनियम में यह स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है कि यह उस तारीख से लागू होगा जिसे केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित कर सकती है। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, यह अधिनियम 26 अक्टूबर, 2006 को लागू हुआ। इस प्रकार, विधायिका ने केंद्र सरकार को उस तारीख को सूचित करने की शक्ति दे दी थी, जिस तारीख से अधिनियम लागू होना था। यह पाठ्यक्रम पं. ऋषिकेश का मामल (सुप्रा) में निर्धारित कानून के अनुसार स्वीकार्य है। इस प्रकार, प्रतिवादी के वकील द्वारा उठाए गए तर्क को आगे बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि अधिनियम 2005 का है और, इसलिए मजिस्ट्रेट 19 जुलाई, 2006 को संज्ञान ले सकता है। यदि ऐसा करने की अनुमति दी जाए तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 के प्रावधानों का उल्लंघन होगा । अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है यह प्रावधान करते हुए कि

[1] 1995(3) RRR 429

किसी भी व्यक्ति को अपराध के रूप में आरोपित कार्य के कमीशन के समय लागू कानून के उल्लंघन के अलावा किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा। इस अनुच्छेद के अनुसार, जब एक निश्चित कार्य उस समय लागू कानून के अनुसार अपराध नहीं होता है जब वह कार्य किया जाता है, तो व्यक्ति जो भी वह कार्य करता है उसे केवल इसलिए अपराध का दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए बाद में ऐसे कार्य को अपराध बनाने के लिए एक कानून बनाया जाता है। जब याचिकाकर्ता पर घरेलू हिंसा अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध करने का आरोप लगाया जाता है, जो ऐसे कृत्यों की तारीख पर लागू नहीं है, तो उक्त धाराओं के तहत आरोप संविधान के अनुचेड़ 20(1) में तय नहीं किया जाएगा। संविधान के 20(1) में कहा गया है कि कथित अपराध किए जाने के समय दंडात्मक प्रावधान अस्तित्व में नहीं थे। वास्तव में, उस समय कोई कानून लागू नहीं था जब याचिकाकर्ता ने कथित तौर पर ये कृत्य किए थे और इसलिए, वह संविधान के अनुचेड़ 20(1) के संरक्षण का हकदार होगा। 26 अक्टूबर, 2006 को अधिनियम लागू होने के बाद, अपराध बनाने वाले अधिनियम के विभिन्न प्रावधान ऐसे अपराध नहीं होंगे जिनके लिए याचिकाकर्ता पर मुकदमा चलाया जा सकता है। 19 जुलाई, 2006 को इस शिकायत के आधार पर संज्ञान लेने की अदालत की कार्रवाई को कायम नहीं रखा जा सकता। इस प्रकार, सम्मन आदेश कायम नहीं रखा जा सकता है और उसे रद्द कर दिया जाता है।

(4) याचिका स्वीकार की जाती है

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उदेश्य के लिए इसके उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उदेशयों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य के लिए उपयुक्त होगा।

सरू गोयल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

पानीपत, हरियाणा